down from 61.28 million tonnes in 1989 to 53.97 million tonnes in 1998;

(b) If so, what are the reasons therefor; and

(c) what are the details of steps taken or proposed to be taken to improve production?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI DILIP RAY): (a) and (b) Yes, Sir. But it should be noted that underground mining is also given due consideration based on factors such as geology of the area, depth of coal deposit, demand of coal, grade of coal and viability of the project. Since nationalisation as many as 100 underground mining projects have been completed which have been replaced some of the exhausting reserves of the on- going mines. 88 underground on-going projects are in operation in Coal India Limited. These 88 on-going projects will yield 36 million tonnes capacity addition on completion. On successful implementation of these projects, Coal India Limited will be able to increase underground coal production from present level of 54 million tonnes to 68 million tonnes by the terminal year of IX Plan 2001-02. In Singareni Collieries Company Limited also, 18 new underground projects were sanctioned during the last 10 years.

(c) Steps taken by Coal India Limited to improve the status of underground mining include mechanisation in Board and Pillar mining, working of Longwall faces in place of conventional manual mining, blasting gallery techniques and introduction of modern and appropriate technologies on 'Risk-Gain' sharing basis through global tendering.

मध्य प्रदेश को कोयले पर रायल्टी

794. **श्री लक्खी राम अग्रवाल:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले चार वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा कोयला खनन के लिए मध्य प्रदेश सरकार को प्रतिवर्ष कितनी रायल्टी राशि दी गई;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कोयला खनन पर रायल्टी राशि बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) पिछले चार वर्षों के दौरान कोयला खनन के लिए कोल इंडिया लि० की अनुषंगी कोयला कंपनियों द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को दी जाने वाली रायल्टी की राशि का वर्षवार ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है;

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने कोककर कोयले की आधार कीमतों के 25% तक तथा डी, ई, एफ और जी ग्रेड के अकोककर कोयले की आधार कीमतों के 25% तक कोयले की रायल्टी दर में संशोधन करने के लिए अभिवेदन दिया है। हाल के वर्षों में आयातित कोयले की खपत में काफी वृद्धि हुई है। यद्यपि आयातित कोयले की लागत की तुलना में भारतीय कोयले की उत्पादन लागत कम है तथापि उच्च भाड़ा प्रभार एवं रायल्टी लेवी भारतीय कोयले की देश में प्रतिस्पर्द्धात्मक को समाप्त कर रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में रायल्टी की दरों में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया जाएगा।

कोयले का कम उत्पादन

795. **श्रीमती मालती शर्मा:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान देश में कोयले का उत्पादन लक्ष्य से कम रहा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उत्पादन पर हुए कुल व्यय की तुलना में कितना राजस्व अर्जित किया गया?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) और (ख) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान कोल इंडिया लि० (कोई०लि०) के लक्ष्य एवं वास्तविक उत्पादन का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:—

(मिलियन टन में)
आंकड़े अनंतिम

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक
1996-97	252.00	250.62
1997-98	260.00	260.55

कोल इंडिया लिमिटेड ने 1997-98 में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। तथापि 1996-97 के दौरान वास्तविक उत्पादन लक्ष्य से थोड़ा कम हुआ है। लक्ष्य प्राप्त न किए जाने के कारणों में अन्य बातों के अलावा, झांजरा और सतग्राम पी एस एल डब्ल्यू फेसेज हेतु लांगवाल की प्राप्ति में हो रहे विलंब, भूमि की अनुपलब्धता, कोटाडीह और मूनीडीह पी एस एल डब्ल्यू फेसेज आदि में गंभीर स्ट्राटा नियंत्रण समस्या शामिल है।

(ग) कोल इंडिया लिमिटेड में पिछले दो वर्षों के दौरान कुल उत्पादन लागत की तुलना में अर्जित राजस्व का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:

(आकंड़े करोड़ रु० में)

	1997-98	1996-97
बिक्री के माध्यम से अर्जित राजस्व (निवल-लेवी छोड़कर)	15,409.33	13,405.76
कोयले का कुल उत्पादन (लागत (रु० टन)	480.81	442.06

Encroachment in Ridge areas by the Defence Ministry

796. SHRI KULDIP NAYYAR: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some complaints regarding the Defence Ministry's encroachment on the Ridge in Delhi have been made, where any kind of construction has been stopped;

(b) if so, how old are the encroachments; and

(c) what action has been taken by Government to remove them?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) to (c) No, Sir. No encroachment had been made nor any constrcution undertaken by the Ministry of Defence on the Ridge in Delhi.

Houses leased by Delhi Cantonment Board

797. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether some houses in Gopinath Bazar Area in Delhi Cantonment have been given on lease to civilians by the Delhi Cantonment Board; if so, the details thereof; and

(b) whether Government have any proposal to shift the said residents to some other areas, by not renewing the said lease; if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) While 14 sites have been given on lease by the Government, no houses in the Gopinath Bazar Area in Delhi Cantonment have been given on lease. Details are given in the Statement (*See* below).

(b) Does not arise.

Statement

S. No.	Survey No.	Date of expiry of the lease term	Remarks
1.	52/1	30.01.1993	Action for renewal
2	52/2	31.01.1993	of those leases
3.	52/4	14.01.2017	which have expired
4.	52/5	28.02.1987	is being taken in
5.	52/6	30.09.2018	some cases the
6.	52/7	30.04.1991	action is held up
7.	52/8	31.08.1990	because of dispute